मांडलगढ़ के भाट खड़ला रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर कई दिनों से सैंडस्टोन का अवैध खनन जारी है। ग्रामीणों की सक्रियता से पुलिस और वन विभाग ने कार्यवाही करके मौके से ट्रैक्टर कम्प्रैशर व क्रेन जब्त किए हैं। बताया जाता है कि, अवैध खनन माफिया ने यहां से करोड़ों रुपए का सैंडस्टोन चुराया है।

रिज़र्व फॉरैस्ट में सैंड स्टोन का अवैध खनन

भीलवाड़ा के भाट खड़ला फॉरैस्ट रिज़र्व में गत कई दिनों से अवैध खनन किया जा रहा है

- ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने घेराबंदी की, इसके बाद खननकर्ता भाग छूटे।
- वन विभाग ने मौके से दो ट्रैक्टर कम्प्रैसर व एक क्रेन को जब्त किया, हालांकि तीन अन्य वाहन थे जिन्हें जब्त नहीं किया गया।

मांडलगढ़, 9 अगस्त (निस)। भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया क्षेत्र के भाट खड़ला में सियासत और सिस्टम की मेहरबानी से आरक्षित वन भूमि में खनन माफिया पिछले कई दिनों से सैंड स्टोन का अवैध खनन कर रहा है।

इस मामले की भनक लगने पर ग्रामीणों ने घेराबंदी की तो अवैध खननकर्ता मौके से भाग छूटे। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और वन कर्मियों को बुलाकर दो ट्रैक्टर कम्प्रैशर व एक क्रेन को जब्त कराया। हालांकि तीन अन्य वाहनों को वनकर्मी बिना जब्त किए मौके पर ही छोड़ कर चले गये।

वाहनों के चालक मौके से फरार हो गए। इस मामले में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की हैं।

ऊपरमाल वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति जलेरी के उपाध्यक्ष रोडू लाल बंजारा के नेतृत्व में बिजौलिया उपखंड अधिकारी सीमा तिवारी को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि, भाट खड़ला खनिज बाउंड्री के ब्लॉक नम्बर 4 की गैप से सटी रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि में खनन माफिया धड़ल्ले से सैंड स्टोन का अवैध खनन कर रहे हैं।

इस मामले की सूचना मेनाल चौकी के कार्यवाहक वनपाल लोकेंद्र सिंह को दी। लोकेंद्र सिंह मय टीम के मौके पर पहुँचे।

अवैध खनन स्थल पर तीन ट्रैक्टर कम्प्रैशर, एक ट्रैलर, एक क्रेन व एक लग्जरी कार मिली। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया ने करोड़ों रुपए का सैंडस्टोन चुराया है तथा वन में वनस्पति एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा हैं, ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर गश्त नहीं करने का आरोप लगाया है।

भाजपा और शिंदे गुट ने मंत्री पदों को आधा-आधा बांटा

मुंबई, 9 अगस्त (वार्ता)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना पदभार संभालने के करीब 40 दिनों के बाद मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 18 नये चेहरों को शामिल किया और इसके साथ ही मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गयी।

मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना के बागी शिंदे गुट के नौ तथा सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के भी नौ विधायक शामिल किये गये। सभी नये मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। कैबिनेट में अब मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस समेत कुल 20 मंत्री हो गये।

शपथ लेने वालों में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए राधाकृष्ण विखे

- 40 दिन के इंतजार के बाद महाराष्ट्र की सरकार का पहला मंत्रिमण्डल विस्तार हुआ।

पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, शिंदे समूह के गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौड़, सुरेश खाड़े, संदीपन भुमरे, उदय सामंत शामिल हैं।

तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभूराज देसाई, मंगलप्रभात लोढ़ा और अन्य शामिल हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मौजूद थे।

शिंदे की नई टीम में सभी के सभी मंत्री करोड़पति हैं। इसमें सबसे ज्यादा संपत्ति मालाबार हिल्स सीट से भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा के पास है।

'अगर सभी बांधों को ईआरसीपी से नहीं जोड़ा तो रोड पर होगी जंग'

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने लालसोट के मीणा हाई कोर्ट में चुनौती दी

- विश्व आदिवासी दिवस पर लालसोट के मीणा हाई कोर्ट में आयोजित जल क्रांति कार्यक्रम में बड़ी तादाद में जुटे लोग तथा कई राजनैतिक हस्तियों ने भी शिरकत की।
- जयपुर कूच के ऐलान से सरकारी तंत्र के हाथ पांव फूले।

लालसोट/दौसा, 9 अगस्त (निसं)। दौसा के नांगल राजावतान में आयोजित मीणा हाईकोर्ट में राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दौसा जिला सहित प्रदेश के सभी बाधों को डीपीआर संशोधन कर बिना भेदभाव के ईआरसीपी परियोजना से नहीं जोड़ा गया तो रोड पर खुले में जंग होगी।

मीणा हाईकोर्ट के जल क्रांति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना को गहलोत सरकार ने राजनीति का मुद्दा बना रखा है जो बिल्कुल गलत है। कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस सरकार में कृषि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री गोलमा देवी, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना, कई विधायक, प्रधान, जिला प्रमुख आदि थे।

जल क्रांति कार्यक्रम को इसके संयोजक राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सहित उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कृषि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, विधायक गजराज खटाना आदि कई नेताओं ने संबोधित किया और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के साथ पूर्वी राजस्थान क्षेत्रों से जुड़े बांधों को राष्ट्रीय परियोजना में जोड़ने की मांग की।

वहीं कार्यक्रम के दौरान विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बाहर से आए कलाकारों गायकों द्वारा पेश किए गए।

हालांकि इससे पूर्व दौसा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, संभागीय आयुक्त सीताराम विकास भाले, दौसा जिला कलैक्टर कमर चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कूच का कार्यक्रम निरस्त करने के लिए काफी मानमनुहार भी की थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर डॉ. मीणा ने सायं 4 बजे जयपुर कूच का ऐलान किया, जिसके बाद सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व मंत्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी अपनी-अपनी गाड़ियों से रवाना हो गये। वहीं हजारों की संख्या लोग हाथों में तिरंगा लेकर ट्रेक्टर, बाईक, निजी वाहनों से उनके पीछे जयपुर के लिए कूच कर गये। तकरीबन 1 घंटे बाद कारवां दौसा बाइपास से जयपुर-आगरा हाईवे पर आ गया। उनके जयपुर कूच को जटवाटा में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। काफिले को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। जटवाडा में करीब एक हजार पुलिसकर्मी, वज्र वाहन, आरएसीए रेपिड एक्शन फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स तैनात की गई है। यहां आईजी उमेश दत्ता, एडीजी विजिलेंस बीजू जॉर्ज जोसेफ, संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले, दौसा जिला कलैक्टर कमर चौधरी, दौसा एसपी संजीव नयन पहले से ही मोर्चा सभाले हुये थे। इधर कूच रोके जाने के दौरान डॉ. किरोडीलाल मीणा समर्थकों एवं पुलिसकर्मियों के बीच काफी गहमागहमी हुई, समर्थकों ने जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया।

वार्ता के लिए मंगलवार को सायं 6 बजे दौसा जिला प्रभारी मंत्री विश्वेन्द्रसिंह जटवाडा में स्थित लक्ष्मी निवास होटल पहुंचे, लेकिन देर सांय तक वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया।

काले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं के काले कपड़े पहनने की भर्त्सना करने वाले गृह मंत्री अमित शाह को मंगलवार को आड़े हाथ लिया। राहुल और कांग्रेसी नेताओं ने संसद भवन परिसर में और कीमत वृद्धि, बेरोजगारी और आवश्यक खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जी.एस.टी. के विरूद्ध दिल्ली में गत शुक्रवार को दी गई गिरफ्तारियों के दौरान काले कपड़े पहन रखे थे।

कांग्रेस नेताओं के काले वस्त्र पहनने को अमित शाह ने भारत की आस्था का अपमान करना बताया और कहा कि वर्ष 2020 में इसी दिन, "अयोध्या दिवस" को प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, इस दिन काले वस्त्र पहनना भगवान राम का अपमान है। इस पर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा दो अवसरों पर ऐसे ही काले कपड़े पहने जाने की याद दिलाई। शर्मा ने प्रश्न किया कि "जब मोदी ऊपर से लेकर नीचे तक काले वस्त्र पहनकर पवित्र गंगा नदी में नहा रहे थे तब क्या वे गंगा मां का अपमान कर रहे थे" और जब वे काले कपड़े पहनकर जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क में घूम रहे थे तब क्या वे वन देवता का अपमान कर रहे थे।" उन्होंने आगे कहा कि "भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में 50वें पायदान पर पहुंच गया है, उस बात की चिंता करना ज्यादा बेहतर होगा।"

भारत जोड़ो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तर्ज पर की जाएगी, जो 7 सितम्बर को ही 80 वर्ष पहले शुरू हुआ था और जिसके बाद भारत ने अन्ततः स्वतंत्रता प्राप्त की थी। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश और प्रवक्ता गौरव गोगोई ने यहां एक प्रैस कांफ्रेंस में बताया कि पदयात्रा करीब पांच महीने चलेगी और 12 राज्यों और-और केन्द्र शासित प्रदेशों में 3 हजार 500 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेगी जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भाग लेंगे। इस विशाल जुलूस में भाग लेने के इच्छुक सभी लोगों से उन्होंने कांग्रेस की तरफ से अपील की कि यह एक विशाल राष्ट्रीय उद्यम है जो भय की राजनीति, धर्मान्धता और पूर्वाग्रह के साथ ही आजीविका विनाश की अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी एवं असमानताओं का एक विकल्प हैं।

जयराम रमेश ने एक ट्वीट में ध्यान दिलाया कि जब महात्मा गांधी ने "भारत छोड़ो" महाआंदोलन शुरू किया था तब आर.एस.एस. ने स्वयं को इस ऐतिहासिक दिन से अलग कर लिया था। उन्होंने रेखांकित किया कि "इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भाग नहीं लिया था जबकि गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद, राजेन्द्र प्रसाद, पंत और कई अन्य नेता व आम लोग जेल गए थे।"

इस बीच, राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के जंगल-जमीन अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके इन अधिकारों को छीनने के लिए सरकार नए कानून लेकर आई है। उन्होंने आगे कहा कि "विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मैं वादा करता हूँ कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया जाएगा। जय जौहर।"

राहुल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के 10 अगस्त को तिजारा आने की जानकारी मिली है लेकिन अभी उनके कार्यक्रम के बारे में विस्तृत और अधिकृत जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि, 10 अगस्त को शिविर का समापन है और राहुल गांधी समापन सत्र को संबोधित कर सकते हैं। शिविर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री शैलजा भी आई जिन्होंने संगठन की मजबूती पर संवाद किया और कहा कि कांग्रेस संगठन को जागरूकता के माध्यम से मजबूती देनी होगी। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास पर जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस देश का सबसे पुराना संगठन है जिसने देश की एकता एवं अखण्डता के लिये हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इधर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रिपु दमन गुप्ता ने बताया कि, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी तिजारा पहुंचे और देर रात तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

यह पहला मौका नहीं, सातवीं बार है जब नीतीश ने अचानक पाला बदला है

कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो उन्हें "कुर्सी कुमार" तक कहने लगे हैं, क्योंकि गठबंधन बदल जाता है लेकिन कुर्सी उनके हाथ में ही रहती है

- इससे पहले भी वे 2013 में एन.डी.ए. को छोड़कर आर.जे.डी. और कांग्रेस के साथ चले गए थे। फिर 2017 में एक बार फिर से भाजपा के साथ चले आए थे।

पटना, 9 अगस्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया है और एक बार फिर से वह आर.जे.डी., कांग्रेस और लेफ्ट दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह फैसला अचानक ही लिया है, जिसने बिहार समेत देश भर के लोगों को चौंका दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो उन्हें "कुर्सी कुमार" तक कहने लगे हैं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है, जब नीतीश कुमार ने इस तरह से अपना रुख बदला है। इससे पहले भी वह 2013 में एन.डी.ए. को छोड़कर आर.जे.डी. और कांग्रेस के साथ चले गए थे। फिर 2017 में एक बार फिर से भाजपा के साथ चले आए थे। इस तरह वे राजनीति में कई बार पाला बदल चुके हैं।

नीतीश कुमार की बिहार में एक अच्छी छवि है और उसके बूते ही वह जे.डी.यू. से ज्यादा सीटें जीतने वाली आर.जे.डी. और भाजपा को अपनी शर्तों पर साधते रहे हैं। नीतीश कुमार ने कई बार राजनीतिक पंडितों को अब अपने पैंतरों से चौंकाया है। 2005 में भाजपा संग बिहार की सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने पहली बार 2012 में चौंकाया था। वह एन.डी.ए. में थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था। इसके बाद 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पी.एम. कैंडिडेट घोषित किया तो नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने रिश्ते को ही खत्म कर दिया था।

जे.डी.यू. ने उसके बाद 2014 का आम चुनाव आर.जे.डी. के साथ ही मिलकर लड़ा था, लेकिन भाजपा की लहर में करारी हार हुई। तब नीतीश कुमार ने चौंकाते हुए मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया था और फिर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। जे.डी.यू. को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से महज 2 पर ही जीत मिली थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन संग उतरने का फैसला लिया था और जीत भी हासिल की थी। यही नहीं जून 2017 में जब वह महागठबंधन के साथ तो राष्ट्रपति चुनाव में यू.पी.ए. की मीरा कुमार की बजाय एन.डी.ए. के रामनाथ कोविंद को वोट दिया था।

अजीब संयोग है: भारत में गांधी...

- ट्रम्प का खेमा इस छापे को वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को भयभीत करने की साजिश बता रहा है।
- ट्रम्प इन छापों को आधार बना कर, पुनः राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की कोशिश में हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सर्किल और उनके घर के अंदरूनी लोगों ने सारे कार्यकलापों की बैकग्राउण्ड ब्रीफिंग और सूचना एफ.बी.आई. को दी थी।

खबरों के अनुसार यह वही क्लब एरिया है जो एफ.बी.आई. जाँचकर्ताओं के संदेह का मुख्य स्थल था और बेसमैंट के स्ट्राँगरूम्स की तलाशी ली गई जहाँ ट्रक भर मिले दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया।

ट्रम्प इसके जवाब में कह रहे हैं कि नौकरशाहों को उनके घर और क्लब में घुसने तथा उनकी तिजोरी को तोड़ने "हथियार के रूप में काम में लिया जा रहा है।" विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रम्प एफ.बी.आई. जाँच का राजनीतिकरण कर रहे हैं ताकि वे इसे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी वापसी का कारण बना सकें।

एफ.बी.आई. यह जाँच कर रही है कि क्या ट्रम्प वाइट हाउस से कुछ संवेदनशील कागज़ात फ्लोरिडा-स्थित अपने घर ले गये थे। संवेदनशील कागज़ातों को सरकारी कार्यालयों/ भंडारों से अपने निजी घरों या दफ्तरों में ले जाना एक "फैडरल" अपराध है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कागज़ात गलत हाथों में पहुँच जायें तो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बन सकते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति के निजी स्टाफ ने इस बात के प्रमाण दे दिये हैं कि दूसरी बार के चुनाव में मिली हार के बाद, ट्रम्प क्रोधोन्माद से भरे हुये थे तथा उन्होंने झूठे दावे करते हुये, परिणामों को विकृत एवं रद्द कर देने की कोशिश तक की थी।

इस देश में जो कुछ हो रहा है, उसके साथ ही देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों की भी जाँच-पड़ताल हो रही है तथा अमेरिका की जाँच एजेंसियाँ उनके आवासों तथा निजी दफ्तरों पर छापे मार रही है। इन तमाम कार्यवाहियों को निजी स्वतंत्रता के साथ एक प्रकार का समझौता माना जा रहा है तथा सरकार सरकारी एजेंसियों का उपयोग पूर्व राजनेताओं को डराने-धमकाने के लिये कर रही है।

एफ.बी.आई. इन आरोपों की प्रतिक्रिया में हरकत में आई है कि संवेदनशील जानकारियाँ तथा दस्तावेज इधर से उधर किये जा रहे हैं। जिस समय एफ.बी.आई. छानबीन एवं जाँच-पड़ताल कर रही थी, उस समय, अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखाकार (नैशनल आर्काइन्स) के प्रतिनिधि भी उसके साथ मौजूद थे। एफ.बी.आई. अपने साथ कागज़ात तथा दस्तावेजों से भरे हुये कम से कम 17 ट्रक अपने साथ ले गई है।

वाइट हाउस के कुछ पूर्व सहायकों ने डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा कुछ संवेदनशील दस्तावेजों को निपटाने तथा अपने निजी स्टाफ से व्यवहार रखने के बारे में भी बताया है। उनके एक पूर्व सहायक ने कहा कि ट्रम्प को दस्तावेजों के टुकड़े-टुकड़े करते तथा उसके बाद उन्हें टॉयलेट के फ्लश में बहाते देखा गया था। इस प्रकार की घटनाओं के इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं।

इस प्रकार के सरकारी भ्रष्ट व्यवहार के सबूतों के बावजूद, रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प का परित्याग नहीं कर रही है और ऐसी भी आशंका है कि ट्रम्प 2024 के चुनाव में एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिये खड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि ये चीजें मध्यावधि चुनाव परिणामों को साफतौर पर प्रभावित कर सकती हैं।

समलैंगिकों को भी मिलेगा बच्चा गोद लेने का अधिकार?

नई दिल्ली, 9 अगस्त। संभव है कि, बहुत जल्द समलैंगिक एवं ट्रांसजैंडर्स इत्यादि को बच्चा गोद लेने की कानूनी अनुमति मिल सकेगी। दरअसल में समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार देने के पहलुओं को परखने के एक संसदीय समिति गठित की गई है। यह संसदीय समिति इस विषय पर विचार कर रही है कि समलैंगिकों एवं ट्रांसजैंडर्स को भी क्या बच्चा गोद लेने का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिये।

विशेषज्ञों का कहना है कि कानून व्यक्ति के यौन झुकाव के आधार पर बच्चा गोद लेने पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन समलैंगिक एवं ट्रांसजैंडर समुदाय के सदस्य दम्पती के रूप में बच्चा तभी गोद ले पाएंगे, जब देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाए, क्योंकि बिना शादी के साथ रहने वाले (लिव-इन) जोड़ों को देश में बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं है।

नीतीश कुमार ने मोदी-शाह द्वय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जायसवाल ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा, "नीतीश कुमार ने बिहार की जनता तथा भाजपा के साथ विश्वासघात किया है। जनता, उन्हें सबक जरूर सिखायेगी।"

दोनों पार्टियों के बीच के तनाव के संबंध-विच्छेद की स्थिति तक पहुँचने के पीछे नीतीश कुमार की यह चिन्ता रही कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता दल (यूनाइटेड) को तोड़ने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं।

इसके लिये, नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता आर.सी.पी. सिंह पर दोषारोपण करते हुए कहा कि वे अमित शाह के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। जब आर.सी.पी.सिंह की पार्टी ने ही उन पर घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो उन्होंने जे.डी. (यू.) से इस्तीफा दे दिया।

2021 में, आर.सी.पी. सिंह, नीतीश कुमार की पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल हुये थे। बिहार के मुख्यमंत्री केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में उनकी पार्टी को केवल एक सीट दिये जाने पर बहुत अशांत हुये थे। कल, उनके निकटतम सहायक ने कहा कि आर.सी.पी. सिंह केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में अपनी इच्छा से शामिल हुये थे तथा उन्होंने नीतीश कुमार को सूचित किया था कि अमित शाह ने कहा है कि मंत्रिमण्डल में जे.डी.यू. के प्रतिनिधि के रूप में केवल वे ही स्वीकार्य हैं। जे.डी.यू. के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा, "क्या हमारी पार्टी के मामले में अमित शाह निर्णय लेंगे?"

बिहार-संकट पर चर्चा करने के लिये, आज बिहार के सबसे बड़े दल, राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) की भी मीटिंग हुई। पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। आशा की जा रही है कि पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन देने की विधिवत घोषणा करेगी तथा पुराना गठबंधन एक बार पुनर्जीवित हो जायेगा। ज्ञातव्य है कि वह गठबंधन सरकार तीन साल से कम समय ही चली थी। सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी यादव नई सरकार में उपमुख्यमंत्री पद सँभालेंगे।

तेजस्वी यादव तथा उनके भाई 2017 तक नीतीश कुमार की उस सरकार में मंत्री थे, जो तीन पार्टियों से मिलकर बनी थीं- जे.डी.यू., आर.जे.डी. तथा कांग्रेस। नीतीश कुमार ने, भाजपा के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को समाप्त करके, आर.जे.डी. तथा कांग्रेस के साथ मिलकर वह गठबंधन सरकार बनाई थी।

लेकिन, लगभग तीन साल बाद, नीतीश ने तेजस्वी यादव और उनके भाई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था तथा इस विवाद के चलते "धर्मनिरपेक्ष" दलों के साथ गठबंधन को तोड़कर, वापस भाजपा की तरफ आ गये थे।

बताया जाता है कि नीतीश कुमार को इस बात का पूरा यकीन है कि अमित शाह बिहार में, महाराष्ट्र-मॉडल को दोहराना चाहते हैं। ज्ञातव्य है कि उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिये मजबूर हो गये थे, उन्हीं की पार्टी शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर शिवसेना एक बड़े विद्रोह के लिये सफलतापूर्वक उकसा दिया था। इसके पुरस्कारस्वरूप, भाजपा ने उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया था।

सूत्रों ने कहा कि नई सरकार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तथा तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बनेंगे तथा नई व्यवस्था के तहत, विधानसभा अध्यक्ष का पद आर.जे.डी. के पास रहेगा।

दोनों गठबंधन पार्टनरों- जे.डी.(यू.) तथा भाजपा के बीच के संबंधों में आई खटास का अंत इन दोनों के संबंध-विच्छेद के रूप में हुआ। इस घटना का असर राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखाई देगा तथा आगामी सप्ताहों और महीनों में राजनैतिक ताकतों का पुर्नसमायोजन सामने आयेगा।

बैंगलोर निगम के चुनाव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है।

काफी पहले ही कर लिये गये सर्वेक्षण म्यूनिसिपल काउंसिल चुनावों में त्रिशंकु जनादेश का संकेत दे रहे हैं क्योंकि मतदाता-विशेषज्ञ आम आदमी पार्टी के "एक्स फैक्टर" बनने की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन शहर में बहुत कम असर होने के बावजूद, जनता दल ने अपनी तैयारियां सबसे पहले शुरू कर दी हैं तथा चुनाव से संबंधित सभी कमेटियाँ बना दी हैं। कांग्रेस ने अपनी सभी शक्तियाँ वरिष्ठ विधायक तथा के.पी.सी.सी. के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी के पीछे तैनात कर दी हैं। भाजपा ने शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायकों के साथ मीटिंग की श्रृंखला का कार्यक्रम बना लिया है। बी.बी.एम.पी. काउंसिल की सदस्य संख्या 302 है तथा महापौर एवं उपमहापौर के पद हासिल करने के लिये किसी भी पार्टी को 152 सदस्यों की जरूरत होगी।

संयोगवश, अगर त्रिशंकु जनादेश की स्थिति आती है तथा किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो, जैसा कि कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों तथा पार्टियों के आकलन है, तो पार्टियों का गठबंधन विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

'आप' के प्रवेश से इस समीकरण में अनिश्चितता का तत्व शामिल हो जायेगा। आप का लक्ष्य 100 सीटों का है तथा वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, जिसके कि म्यूनिसिपेलिटी की सत्ता में उसका महत्व रहे तथा स्थानीय प्रशासन में उसे तवज्जोह मिले।

सत्तारूढ़ भाजपा ने इन सर्वेक्षणों को भ्रामक बताते हुये खारिज कर दिया है तथा कहा है कि ज़मीनी स्थिति काफी हद तक भाजपा के पक्ष में है। भाजपा विधायक उदय गरुड़ाचर के अनुसार, "हम बड़े बहुमत से जीतेंगे।"

कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर इतनी ही आश्वस्त है तथा अभी हाल ही में, पूर्व मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया का जन्म दिन मनाने के उपलक्ष में हुई जनसभाओं की सफलता के बाद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है तथा वे सक्रिय हो गये हैं। ए.आई.सी.सी. के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो जन्म दिन समारोह में शामिल हुये थे, ने सिद्धारमैया तथा के.पी.सी.सी. अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, ताकि वे एकजुट होकर पार्टी के लिये काम कर सकें क्योंकि "कांग्रेस जीतने की स्थिति में है तथा विधानसभा चुनाव की जीत के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में उसके सामने कोई बाधा नहीं है।"

राजनीतिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जे.डी.यू. के बने रहने पर अब भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। यह लगभग तयशुदा है कि 2025 के राज्य विधानसभा चुनावों के दो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी आर.जे.डी. और भाजपा ही रहेंगे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908